साान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02 | अंक - 135 | जौनपुर, शनिवार, 10 फरवरी 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

राबड़ी देवी, हेमा और मीसा भारती को जमानत

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी राबड़ी देवी और उनकी बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुईं। प्रवर्तन निदेशालय ने 4,751 पेज की चार्जशीट दाखिल कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो कंपनियों समेत कुल सात लोगों को आरोपी बनाया है। 28 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या मामले में अमित कत्याल के अलावा किसी और को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट को जवाब देते हुए ईडी ने कहा कि सिर्फ अमित कत्याल को गिरफ्तार किया गया है। सुनवाई के दौरान कात्याल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। सोमवार को, दिल्ली की एक अदालत ने अमित कत्याल को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई सदस्यों से जुड़े नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। कात्याल को पहले हिरासत में लिया गया और बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 11 नवंबर, 2023 को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि कात्याल ने राजद प्रमुख और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री की ओर से कई उम्मीदवारों से जमीन अधिग्रहण की थी।

कुछ लोग भारत को धर्मनिरपेक्ष से धार्मिक राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे – विजयन

नई दिल्ली, एजेंसी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शुक्रवार को कहा कि कुछ लोग, जिनमें संवैधानिक पदों पर बैठे कुछ लोग भी शामिल हैं, बौद्धिक विचार के बजाय "मनगढ़ंत कहानियों" को प्राथमिकता देकर देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से धार्मिक राष्ट्र में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। विजयन ने कहा कि इसलिए सावधानी और सतर्कता से आगे बढ़ने की जरूरत है। यहां 36वीं केरल विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन के बाद कुछ लोग बौद्धिक चिंतन के स्थान पर मनगढ़ंत कहानियों को प्राथमिकता देकर हमारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को धार्मिक राष्ट्र में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्य से संवैधानिक पदों पर बैठे कुछ लोग ऐसे प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "इसलिए, हमें सतर्कता और सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे-जैसे राज्य उत्तरोत्तर और वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ रहा है।

छत्तीसगढ़ का 1.47 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 1,47,446 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि यह गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी या 'ज्ञान' (जीवाईएएन) की समृद्धि पर केंद्रित है। साथ ही इससे बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी। विष्णु देव साई ने दिसंबर में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। साई नीत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के पहले बजट में किसी नए कर की घोषणा नहीं की गई। चौधरी ने राज्य को विकासशील से विकसित राज्य बनाने के मकसद से इस साल एक नवंबर को 'अमृतकालरू छत्तीसगढ़ विजन /2047' नाम से एक दस्तावेज लाने की भी घोषणा की। चौधरी ने 'विजन' दस्तावेज पर कहा कि इसके तहत पहला मध्यावधि लक्ष्य अगले पांच वर्षों में जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) को पांच लाख करोड़ रुपये से दोगुना करके 2028 तक 10 लाख करोड़ रुपये करना होगा। उन्होंने कहा, '' बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित है। इससे पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ–साथ युवाओं के लिए रोजगार तथा आजीविका को बढ़ावा देकर बुनियादी ढांचे के विकास को बल मिलेगा।'' उन्होंने कहा कि बजट 'मोदी की गारंटी' के तहत किए गए (चुनाव पूर्व) वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री ने कहा, पिछले पांच वर्षों में पूर्ववर्ती (कांग्रेस) सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के साथ अन्याय किया। न केवल गरीबों से छत का अधिकार छीना गया, बल्कि खाद की कालाबाजारी, दो रुपये प्रति किलोग्राम गोबर की खरीद और 10 रुपये प्रति किलोग्राम में जबरन घटिया खाद (गाय के गोबर से तैयार) बेचने का भी काम किया गया।'' मंत्री ने दावा किया कि पूर्ववर्ती सरकार ने महिलाओं को 500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा करने में विफल रही। उन्होंने कहा, '' दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी जो पिछले साल 7,000 रुपये थी।'' मंत्री ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख मकानों के निर्माण के लिए 8,369 करोड़ रुपये, छोटे तथा मझोले किसानों को मजबूत करने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये और जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चौधरी ने कहा, '' राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है (जिसके तहत विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे)। श्री राम लला दर्शन (अयोध्या धाम दर्शन) के लिए नागरिकों के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना लागू की जाएगी। मंत्री ने कहा, '' रायपुर और भिलाई शहरों को शामिल करते हुए एक राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) की स्थापना की जाएगी। सोलर रूफटॉप, ई–वाहनों को प्रोत्साहन, कुसुम योजना सहित अन्य पर्यावरण अनुकूल योजनाओं को अपनाने के अलावा कार्बन

उत्सर्जन में कमी के लिए एक जलवायु कार्य योजना तैयार की जाएगी।'' चौधरी ने कहा कि 'इन्वेस्ट छत्तीसगढ़' कार्यक्रम के आयोजन के लिए बजट में पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, '' वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कोई कर प्रस्ताव नहीं है और मौजूदा कर दरों में कोई वृद्धि नहीं है। सकारात्मक प्रयासों के परिणाम स्वरूप, राज्य के स्वयं के राजस्व में नए कर लगाए बिना या कर दरों में वृद्धि के बिना 22 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

द ग्रैंड सेंट्रल पार्क अब नमो - द ग्रैंड सेंट्रल पार्क के नाम से जाना जाएगा - सीएम एकनाथ शिंदे

ठाणे, एजेंसी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहद अहम ग्रांड सेंट्रल पार्क की संकल्पना पहली बार ठाणे में साकार हुई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को ठाणे में कहा कि यह उद्यान युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आनंददायक साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने ठाणे महानगरपालिका और कल्पतरु समूह द्वारा विकसित किए गए ग्रैंड सेंट्रल पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि द ग्रैंड सेंट्रल पार्क को अब ष्नमो – द ग्रैंड सेंट्रल पार्क के नाम से जाना जाएगा। विधायक संजय केलकर के सुझाव के अनुसार उद्यान का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दिया जाएगा। इसलिए इस पार्क को ष्नमो द ग्रैंड सेंट्रल पार्कश के नाम से जाना जाएगा। ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र में कोलशेत क्षेत्र में 20.5 एकड़ जमीन पर साकार हुए द ग्रैंड सेंट्रल पार्क सेंट्रल का लोकार्पण समारोह के दौरान स्कूली शिक्षा व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, विधायक श्री केलकर, विधायक प्रताप सरनाईक, जिलाधिकारी अशोक शिनगारे, मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर, अतिरिक्त आयुक्त (1) संदीप मालवी, अतिरिक्त आयुक्त (2) प्रशांत रोडे, उपायुक्त उमेश बिरारी, उपायुक्त मिताली संचेती, कल्पतरु डेवलपर्स के मोफतराज मुनोत आदि उपस्थित थे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने पार्क का निरीक्षण किया। इसकी संकल्पना के आधार पर विभिन्न देशों के पार्कों, खिलौनों और स्थानों का निरीक्षण किया गया। क्यूआर कोड को स्कैन कर पेड़ के बारे में भी जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री श्री ने कहा कि यह राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है। इसके निर्माण में कहीं भी गुणवत्ता से समझौता नहीं किया गया है। इस पार्क में लगभग 3 हजार 500 पेड़ हैं। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की योजना बनाई जानी चाहिए। साथ ही इसका प्रबंधन भी सुव्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए। इंजेनियस डेवलपर्स ने इसे टीडीआर के जरिए बनाया है। ये उद्यान महानगरपालिका का कोई पैसा खर्च किए बिना बनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि अर्बन पाक कैसा हो सकता है।

जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग

नयी दिल्ली, एजेंसी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से यहां मुलाकात की और राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग की। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने भी सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जगन और मोदी की मुलाकात की जानकारी दी। रेड्डी 2019 के विधानसभा चुनाव में राज्य को विशेष दर्जा दिलाने की मांग के वादे के साथ सत्ता में आए थे और इस मुद्दे पर पहले भी प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि आंध्र प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा अपनी स्थिति मजबूत करने और तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के

भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने की संभावना के बीच रेड्डी आखिरी कोशिश के तहत राष्ट्रीय राजधानी आए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संसद परिसर में प्रधानमंत्री से मुलाकात की और लंबित योजनाओं पर चर्चा की और राज्य को विशेष दर्जा देने सहित विभिन्न मांग रखी। विशेष श्रेणी का दर्जा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों में से एक है, जिसके जरिये जून 2014 में अलग तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था।

तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू द्वारा आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा से संभावित गठबंधन पर बातचीत के लिए शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के कुछ दिनों बाद हो रहा है।

एनडीए की सरकार जरूर है, हमारा संकल्प भाजपा की सरकार बनानी है – सम्राट चौधरी

पटना, एजेंसी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गुरुवार को साफ कर दिया कि आज बिहार में एनडीए की सरकार जरूर है, लेकिन हमारा संकल्प भाजपा की सरकार बनाने की है। सम्मान सह संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार में एनडीए सरकार बनने की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार की सत्ता से जंगलराज के प्रणेता को हटाने के लिए भाजपा ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। इस मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने अपने स्थान पर खड़े होकर एक मिनट तक ताली बजाकर पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार में उप

मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और मंत्री बने प्रेम कुमार को सम्मानित किया गया तथा 2024 में बिहार के सभी 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतने का संकल्प भी लिया गया। चौधरी ने कहा कि भाजपा मंडल का भी समर्थन करती है कमंडल का भी समर्थन करती है। अगर आज हम सरकार में शामिल हैं तो इसका क्रेडिट कार्यकर्ताओं को जाता है। भाजपा गठबंधन जरूर करती है लेकिन बदलती नहीं है।

चुनावों में असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ही यूसीसी लाया गया - हरीश रावत

देहरादून, एजेंसी। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किए जाने की पृष्ठभूमि में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को कहा कि देश में केंद्रीय स्तर पर यूसीसी लाने की योजना को ठंडे बस्ते में डाले जाने के बाद भाजपा इस विधेयक को उत्तराखंड में लाई ताकि आगामी आम चुनावों के दौरान महंगाई, बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान हट जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूसीसी पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए लाया गया है ताकि जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, बिगड़ती कानून–व्यवस्था, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार जैसे असली मुद्दों से हटाया जा सके। उन्होंने कहा, "यह केवल एक राजनीतिक शिगूफा है।" रावत

ने यहां कहा कि भाजपा ने पहले राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी लाने का प्रयास किया और मामले को राष्ट्रीय विधि आयोग को सौंप दिया। रावत ने यहां पीटीआई– से एक खास बातचीत में कहा, "इसके बाद यूसीसी को केंद्रीय स्तर पर लाने की योजना ठप कर दी गयी और इसे लाने के लिए उत्तराखंड को चुना गया।" उन्होंने दावा किया कि पूर्वोत्तर सहित कई जगहों पर आदिवासी समुदायों द्वारा अपनी परंपराओं में इसे हस्तक्षेप मानते हुए इसका विरोध किया गया जबकि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी और दक्षिण भारत से भी इसके विरोध में स्वर उठे। उन्होंने कहा कि आदिवासी समूहों की नाराजगी को समाप्त करने के लिए ही भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करने वाली पहली विधानसभा बन गई है। अब अन्य सभी विधिक प्रक्रिया और पूरी की जाएंगी जिसके बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

मोदी सरकार ने 'राष्ट्र प्रथम' रखकर संकट की स्थिति से देश को निकाला – निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को फ्रैजाइल फाइव श्रेणी से बाहर निकालने के बाद श्वेत पत्र रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जनजीवन पर उसके प्रभाव पर श्वेतपत्र लोकसभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक 'श्वेत पत्र' लोकसभा में पेश किया था। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि श्वेतपत्र में 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट से निपटने के पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के तरीके और कोविड–19 के भयावह हालात से निपटने के मोदी सरकार के तरीकों की तुलना की गई है। निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि मोदी सरकार ने 'राष्ट्र प्रथम' रखकर संकट की स्थिति से देश को निकाला, पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के समय देश को प्रथम नहीं रखा गया, बल्कि उनके प्रथम परिवार को आगे रखा गया। उन्होंने कहा कि एक सरकार के 10 साल कुछ संकट के साथ और 10 साल एक अलग सरकार के 10 साल अलग संकट के साथ। इस श्वेत पत्रश में दिखाई गई तुलना स्पष्ट रूप से बताती है कि अगर सरकार इसे सच्ची ईमानदारी, पारदर्शिता और राष्ट्र को पहले रखकर संभालती है, तो परिणाम सबके सामने हैं। उन्होंने कहा कि जब आप राष्ट्र को पहले नहीं रखते, जब आप अपने परिवार को पहले रखते हैं, और जब आपके पास पारदर्शिता के अलावा अन्य विचार होते हैं, तो परिणाम आपके सामने हैं। तो 2008 के बाद जब वैश्विक वित्तीय संकट आया और उसके बाद जो कुछ हुआ, उससे स्पष्ट है कि यदि सरकार की मंशा ईमानदार है तो परिणाम अच्छे होंगे।

मुझे जितनी संख्या में समन भेजे जाएंगे उतनी ही संख्या में स्कूल खोलूंगा - सीएम केजरीवाल

नयी दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना उनकी सरकार का लक्ष्य है और जांच एजेंसियां जितनी संख्या में उन्हें समन भेजेंगी, वह उतनी ही संख्या में राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल खोलेंगे। मयूर विहार फेज–3 में एक सरकारी स्कूल भवन की आधारशिला रखने के बाद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ अपनी सारी जांच एजेंसियों को ऐसे लगा रखा है, जैसे कि वह देश के 'सबसे बड़े आतंकवादी' हों। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक मामले के सिलसिले में 17 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत में पेश होने को कहा गया है। केजरीवाल, कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए संघीय एजेंसी द्वारा उन्हें जारी पांच समन को टाल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने से एक पीढ़ी में गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार स्कूल खोल रही है। उन्होंने कहा, "दिल्ली में आप सरकार बनने के बाद से हमने कई शानदार स्कूल खोले हैं। हाल में बुराड़ी, रोहिणी और पालम समेत कई नये स्कूलों का उद्घाटन किया गया है, जिनमें 1.5 लाख बच्चों को शिक्षा मिलेगी।" केजरीवाल ने कहा कि नये स्कूलों में प्रयोगशाला, पुस्तकालय और गतिविधि कक्ष सहित सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा होगा। उन्होंने कहा, "हम सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के डॉ. (भीम राव) आंबेडकर के सपने को पूरा कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि दो साल पहले उनकी सरकार ने घर–घर राशन पहुंचाने की योजना का प्रस्ताव किया था लेकिन केंद्र ने इसकी अनुमति नहीं दी। आप नेता ने कहा, "उन्होंने उपराज्यपाल के माध्यम से इसमें बाधा डाली। लेकिन हम शनिवार से पंजाब में घर–घर राशन पहुंचाने जा रहे हैं।" केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में इस योजना के शुरू होने के बाद इसे दिल्ली में भी लागू किया जा सकता है। और केंद्र इसे रोक नहीं सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने दिल्ली को आधा राज्य बताकर आप सरकार के कामकाज में कई बाधाएं डाली हैं।

संपादकीय

दालों का महत्व

पर्यावरण–संरक्षण, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास एवं खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये हर साल 10 फरवरी का दिन दुनियाभर में विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसका मकसद लोगों को दालों के फायदे और महत्व के बारे में बताना होता है। दालें, जिनमें दाल, छोले, बीन्स और मटर शामिल हैं, जो प्रोटीन से लेकर फाइबर, आयरन जैसे कई जरूरी पोषक तत्वों के साथ विटामिन्स और मिनरल्स का भी खजाना होती हैं। दालें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में भी खानपान का जरूरी हिस्सा हैं। शाकाहारी जीवनशैली के लिए तो दालें ही प्रोटीन का सबसे बड़ा स्त्रोत हैं। कम वसा वाले और कम सोडियम वाले इस ऑप्शन को डाइट में शामिल कर न केवल असाध्य बीमारियों से लड़ा जा सकता है बल्कि जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के संकट से भी बचा जा सकता है। इस साल 2024 में विश्व दलहन दिवस की थीम "दालें: पौष्टिक मिट्टी और लोगों" रखी गई है। इस थीम का मतलब स्वस्थ मिट्टी और स्वस्थ लोगों की कुंजी के रूप में दालों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व स्तर पर दलहन की उपयोगिता एवं प्रासंगिता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 20 दिसंबर 2013 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मानने का निर्णय लिया गया, जो पहली बार साल 2016 में मनाया गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी 2019 को विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दालों का उत्पादन बढ़ाकर दुनिया में गरीब कुपोषित देशों को पोषक तत्वों से भरपूर खाना उपलब्ध करवाना था क्योंकि दालों में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। दालें न केवल पोषक हैं, वे विश्व की भूख और गरीबी को मिटाने की दिशा में स्थायी खाद्य प्रणालियों के विकास में भी योगभूत हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यह सतत विकास के लिए अपने 2030 एजेंडा को हासिल करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है, जिसका उद्देश्य वैश्विक शांति को मजबूत करना और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। मांसाहार पर्यावरण के सम्मुख एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि एक किलो दाल के उत्पादन के लिए 1250 लीटर पानी की जरूरत होती है, जबकि एक किलो बीफ के लिए 13,000 लीटर की जरूरत होती है। देश–विदेश में भी दालों का प्रचलन एवं महत्व कम नहीं है, लेकिन परम्परागत भारतीय भोजन में पौष्टिकता के कारण दालों का विशेष महत्व है। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी ने दलहन क्रांति की कवायद शुरू कर दी। सरकार ने दालों के घरेलू उत्पादन बढ़ाने के उपाय सुझाने हेतु सुब्रमण्यम समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लंबे समय से भारतीय खेती में अन्य अनाजों की तुलना में दालों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। महंगी दालों ने आम आदमी की थाली से दाल को तकरीबन दूर ही कर दिया था, लेकिन मोदी की कोशिशों से अब आम आदमी की थाली में दालें भरपूर मात्रा आ गई हैं। मोदी सरकार द्वारा दलहनी फसलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों का ही नतीजा है कि 2015–16 में जहां 163 लाख टन दालों का उत्पादन हुआ था, वहीं दो साल बाद 2017–18 में यह बढ़कर 239. 5 लाख टन हो गया। इससे दालों का आयात तेजी से कम हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दालों के महत्व को देखते हुए इसके उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिये अभियान चला रखा है। 'दाल रोटी खाओ–प्रभु के गुण गाओ' लोकोक्ति से स्पष्ट है कि दालें सम्पूर्ण भोजन के रूप में हमारी जीवन संस्कृति एवं समृद्ध खानपान में शामिल रही हैं। इतना ही नहीं, देश के अलग–अलग भू–भागों में दालों की विभिन्नताओं के साथ–साथ उनके उपयोग की भी विशिष्ट प्रकृति रही है। जबकि भारतीय खेती की बदहाली की एक बड़ी वजह एकांगी कृषि विकास नीतियां रही हैं। वोट बैंक की राजनीति के कारण सरकारों ने गेहूं, धान, गन्ना, कपास जैसी चुनिंदा फसलों के अलावा दूसरी फसलों पर ध्यान ही नहीं दिया। इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव दलहनी व तिलहनी फसलों पर पड़ा। घरेलू उत्पादन में बढ़ोत्तरी न होने का नतीजा यह हुआ कि दालों व खाद्य तेल का आयात तेजी से बढ़ा। दाले भारतीय भोजन की थाली का सौन्दर्य एवं स्वाद रही है। न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की सांस्कृतिक परंपराओं और व्यंजनों में दालें गहराई से अंतर्निहित हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उड़द व छोले, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व बंगाल में अरहर तथा महाराष्ट्र एवं दक्षिणी राज्यों में मसूर दाल का इस्तेमाल विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है। दालों का उपयोग विभिन्न रूपों में समूचे देश में होता है। देश भर में उत्पादित होने वाली दालों में 44.51 फीसदी हिस्सा चने का है। वहीं अरहर 16.84 प्रतिशत, उड़द 14.1 प्रतिशत, मूंग 7.96 प्रतिशत, मसूर 6.38 प्रतिशत तथा शेष दालों की 10.18 फीसदी पैदावार होती है। इसके बावजूद हमारे आहार में दालों की उपलब्धता कम होना विचारणीय है। पर्यावरणीय लाभों की दृष्टि से दालों की पैदावार एवं उपयोग आधुनिक खानपान का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि दालों के नाइट्रोजन–स्थिरीकरण गुण मिट्टी की उर्वरता में सुधार करते हैं, जो खेत की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। इंटरक्रॉपिंग और कवर फसलों के लिए दालों का उपयोग करके, हानिकारक कीटों और बीमारियों को दूर रखते हुए, किसान खेत और मिट्टी की जैव विविधता को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा, मिट्टी में कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन डालने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिंथेटिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करके दालें जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान दे सकती हैं।

ट्रैक बदलने से पूर्व रेलवे बॉस ने ट्राई को दी दूरदृष्टि

ललित

अंदाजा लगाओ कि नई टोपी किसने पहनी है? रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लाहोटी हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के प्रमुख बने हैं। एक शानदार कैरियर के साथ एक अनुभवी रेलवे अधिकारी, उनकी नियुक्ति विभिन्न क्षेत्रों में कौशल की बहुमुखी प्रतिभा और हस्तांतरणीयता को दर्शाती है। रेलवे क्षेत्र का नेतृत्व करने से लेकर दूरसंचार नियामक संस्था का नेतृत्व करने तक का परिवर्तन पहली नजर में अपरंपरागत लग सकता है। लेकिन श्री लाहोटी सामान्य रेलवे वाले नहीं हैं। रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ के रूप में उनके कार्यकाल ने जटिल बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के प्रबंधन में उनकी निपुणता को प्रदर्शित किया। वह आनंद विहार टर्मिनल और नई दिल्ली में अजमेरी गेट साइड स्टेशन बिल्डिंग जैसी परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण थे। वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को एक विश्व स्तरीय स्टेशन रेलवे के रूप में पुनर्विकास करने की योजना से भी निकटता से जुड़े थे, जिसमें भूमि का वाणिज्यिक विकास भी शामिल था। श्री लाहोटी का परियोजना प्रबंधन और रणनीतिक योजना में व्यापक अनुभव उन्हें एक अद्वितीय कौशल सेट से लैस करता है। और अब उनकी नजर टेलीकॉम जगत पर है। उनकी नियुक्ति न केवल क्षेत्रों को जोड़ती है, बल्कि विशिष्ट डोमेन से परे नेतृत्व गुणों के महत्व पर भी प्रकाश डालती है, जो नवाचार और विकास की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों को संचालित करने में एक पूर्ण और दूरदर्शी नेता के मूल्य पर जोर देती है। अपनी सीट बेल्ट बांधें दृ श्री लाहोटी आपके कॉल और डेटा में रेलवे का माहौल ला रहे हैं!

16वें वित्त आयोग की संरचना के संबंध में हालिया घोषणाएं मोदी सरकार द्वारा रणनीतिक नियुक्तियों की एक दिलचस्प तस्वीर पेश करती हैं। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति ने आयोग के चार सदस्यों को शामिल करने के लिए मंच तैयार किया। दिलचस्प बात यह है कि नए आयोग के दो पूर्णकालिक सदस्य वित्त मंत्रालय के पूर्व अधिकारी हैं। अजय नारायण झा, एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, आयोग में अनुभव का खजाना लेकर आते हैं। व्यय सचिव के रूप में उनकी पूर्व भूमिका और 15वें वित्त आयोग में भागीदारी उन्हें एक मूल्यवान संपत्ति बनाती है। एनी जॉर्ज मैथ्यू, व्यय विभाग में पूर्व विशेष सचिव, श्री झा के साथ पैनल में शामिल हो गए हैं, और उनकी संयुक्त विशेषज्ञता वित्तीय मामलों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का संकेत देती है, जो कार्य की सूक्ष्म समझ का सुझाव देती है। एक दिलचस्प मिश्रण में, अर्था ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक डॉ. निरंजन राजाध्यक्ष, वित्तीय नियोजन के विविध दृष्टिकोण पर जोर देते हुए, आयोग के विचार–विमर्श में निजी क्षेत्र का परिप्रेक्ष्य लाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य कार्यकारी सलाहकार डॉ. सौम्य कांति घोष, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की अंतर्दृष्टि का एक अनूठा मिश्रण सामने लाते हैं। इस प्रतिष्ठित समूह और इसकी सिफारिशों पर बहुत कुछ निर्भर है, खासकर तब जब राज्यों के बीच राजस्व बंटवारा एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है।

पहली महिला मुख्य सचिव बनीं

1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी की नियुक्ति के साथ उत्तराखंड को पहली महिला मुख्य सचिव मिलीं। उन्होंने बैचमेट सुखबीर सिंह संधू का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल पिछले महीने समाप्त हो गया है। सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर उनका आरोहण न केवल उनकी उपलब्धियों को रेखांकित करता है, बल्कि राज्य के शासन में समावेशिता की दिशा में व्यापक बदलाव का भी प्रतीक है। निश्चित रूप से, भारत ने 1970 के बाद से एक लंबा सफर तय किया है, जब आईएएस में शामिल होने वालों में महिलाएं केवल नौ प्रतिशत थीं। वर्तमान में, 21 प्रतिशत सेवारत आईएएस अधिकारी महिलाएं हैं। कई राज्यों ने समय–समय पर महिलाओं को आईएएस प्रमुख के रूप में देखा है, सबसे हालिया 2022 में राजस्थान में उषा शर्मा हैं, लेकिन संख्या अभी भी इतनी कम है कि ऐसी नियुक्तियां, जब भी होती हैं, चर्चा पैदा करती हैं। उत्तराखंड के शीर्ष प्रशासनिक पद तक अपनी यात्रा में, सुश्री रतूड़ी ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश में और फिर उत्तराखंड में। दिलचस्प बात यह है कि उनके पति, अनिल रतूड़ी, एक आईपीएस अधिकारी, 2020 में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। राज्य, जिसका गठन 2000 में हुआ था, अब अपने प्रशासनिक क्षेत्रों में कांच की छत को तोड़ने के साथ एक परिवर्तनकारी क्षण देख रहा है। इस बीच, भारत को अभी भी अपनी पहली महिला कैबिनेट सचिव का इंतजार है।

आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए यूसीसी रोलआउट

आदित्य

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून में विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक पेश किया। इसके अधिनियम बन जाने पर उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। संविधान के भाग प्ट में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि "राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा"। यूसीसी को विवाह, तलाक, बच्चे की हिरासत, गोद लेने, विरासत और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित मामलों में, धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना, कानूनों के एक सामान्य सेट के उद्देश्य से पेश किया गया है। चूंकि व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्यों को भी उन पर कानून बनाने का अधिकार है। बीजेपी प्रमुख नड्डा ने कहा था कि समान नागरिक संहिता को राज्यों के माध्यम से लागू किया जाएगा. राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश बीजेपी पहले से ही इसकी योजना बना रही है. एक बहुलवादी समाज एक आदर्शवादी समाज है, एक विविधतापूर्ण समाज जहां लोग धार्मिक और अज्ञेयवादी सहित विभिन्न चीजों और परंपराओं में विश्वास करते हैं और उनका अभ्यास करते हैं, फिर भी एक–दूसरे के विचारों, विश्वासों और प्रथाओं को सहन करते हैं, भले ही वे अपने विचारों, विश्वासों और प्रथाओं से मेल नहीं खाते हों। स्वाभाविक रूप से, यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। यह व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनता। भारत वस्तुतः एक ऐसा समाज है। अतीत में विभाजन और वर्तमान में बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण के मद्देनजर, यूसीसी एक विवादास्पद और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बन गया है। फिर भी बीजेपी कुछ प्रावधानों का हवाला देकर महिला समानता को उत्तराखंड यूसीसी बिल से जोड़ रही है. लिव–इन पार्टनर द्वारा छोड़ी गई महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलेगा और लिव–इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे वैध माने जाएंगे। लेकिन, वह पेचीदा मुद्दों पर चुप है. मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937, मुसलमानों के बीच विवाह, तलाक, विरासत और रखरखाव जैसे मामलों को नियंत्रित करता है। एक यूसीसी इसके कुछ प्रावधानों को प्रभावित, प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करेगा। उत्तराखंड यूसीसी बिल में धर्म परिवर्तन को तलाक का आधार बनाने की मांग की गई है, जो विशेष विवाह अधिनियम का उल्लंघन है। यूसीसी लिव–इन पार्टनरशिप पर भी रोक लगाता है जिसका सहारा अंतर–धार्मिक जोड़ों के मामले में सभी औपचारिकताओं को पूरा करने या अपने माता–पिता की मंजूरी प्राप्त करने से पहले किया जाता है। इसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा, जो जोड़े में से किसी एक की उम्र 21 वर्ष से कम होने पर पुलिस को सूचित करेगा दृ लेकिन, यूसीसी खुद कहता है कि एक लड़की 18 साल की उम्र में शादी कर सकती है। अन्यथा, उन्हें कारावास का सामना करना पड़ेगा। विधेयक का विस्तार होता है तलाक के मानदंड पति से लेकर पत्नी तक पर भी लागू होते हैं। महिलाएं बिना किसी शर्त के तलाकशुदा पति या पत्नी से दोबारा शादी कर सकती हैं, जैसे कि "इस तरह के पुनर्विवाह से पहले किसी तीसरे व्यक्ति से शादी करना", इस प्रकार मुसलमानों के कुछ वर्गों द्वारा प्रचलित निकाह हलाला पर रोक लगा दी गई है। फिर से लिव–इन रिश्ते केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच होते हैं, इस प्रकार समान–लिंग वाले जोड़ों के साथ भेदभाव होता है।

मस्जिदों पर नियंत्रण देसी मुसलमानों का हो

सुजीत

यह रहस्य किसी से छिपा नहीं है कि महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक के लगभग छह–सात सौ साल के कार्यकाल में अरबों, तुर्कों और मुगल मंगोलों ने हिंदुस्तान में मंदिरों को ही नहीं गिराया बल्कि बहुत से लोगों को मतांतरित भी किया। बंगाल और सप्त सिंधु पश्चिमोत्तर भारत में यह काम बड़े स्तर पर हुआ। हिंदुस्तान के जो लोग अपने मजहब को छोड़ कर मुसलमान बन गए, उन्हें देसी मुसलमान या डीएम कहा जाता है। आज भारत के कुल मुसलमानों में से 5 फीसदी अशरफ मुसलमानों को यदि निकाल दिया जाए तो शेष मुसलमानों में से 95 फीसदी जनसंख्या देसी मुसलमानों की है। लेकिन अशरफ समाज, जिसे एटीएम भी कहा जाता है (एटीएम से अभिप्राय अरब, तुर्क और मुगल मंगोल से है), का देसी मुसलमानों पर पूरी तरह नियंत्रण है। आज स्थिति यह है कि मस्जिदों में इबादत के लिए देसी मुसलमान जाते हैं और मस्जिदों पर कब्जा अशरफों का है। मस्जिदों में जो चढ़ावा चढ़ता है, वे देसी मुसलमान देते हैं और उसके उपयोग का अधिकार अशरफ के पास है। एटीएम मूल के मुसलमान, जिस संस्था को 'आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' कह कर दिन–रात चिल्लाते रहते हैं, वह दरअसल 'अशरफ क्लब' के सिवा कुछ नहीं है। वह भारत के देसी मुसलमानों को डराने का तमंचा है। अशरफ समाज देसी मुसलमानों पर अरब के उसूल और तहजीब लादना चाहता है। उसी को वह शरीयत कह कर देसी मुसलमानों की गर्दन पर सवार रहता है। शरीयत का जो सामाजिक ताना–बाना है, वह मूल रूप में अरब का कल्चर है। वहां के लोग हो सकता हैं उसके पक्ष में हों। तीन तलाक और हलाला उसी में से उपजा है। भारत का देसी मुसलमान भला हलाला जैसी विदेशी अरबी प्रथा को क्यों स्वीकार करेगा? लेकिन मस्जिद का सैयद मौलवी भारत के देसी मुसलमान को इसका विरोध करने पर उसे डराता है। उसे दोजख की तस्वीरें दिखाता है। दुर्भाग्य से देश की सरकार ऐसे समय में सैयद मौलवी के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है, न कि देसी मुसलमानों के पक्ष में। यदि कोई शाहबानो इन अमानवीय अरबी रीति–रिवाजों और विधि–विधानों से लडने का दम भी दिखाती है तो उस पर दो तरफ से हमला होता है। अशरफ उसे दाएं से घेरता है और सरकार उसे बाएं से घेरती है। तब शाहबानो जीत कर भी हार जाती है और सैयद अशरफ हार कर भी जीत जाता है। पिछले दिनों उत्तराखंड की विधानसभा ने राज्य में समान सिविल कोड पारित किया है। समान सिविल संहिता लागू करने वाला यह दूसरा राज्य बन जाएगा। इससे पहले गोवा समान सिविल कोड का पालन करता है। लेकिन उत्तराखंड में यह कानून पास होने पर सैयद अशरफ कपड़ों से बाहर हो रहे हैं। वैसे संविधान के चौथे अध्याय में सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि यह कानून लागू करना चाहिए। लेकिन एटीएम अशरफ का कहना है कि उसका संविधान शरीयत ही है। काशी के विश्वनाथ मंदिर के आधे हिस्से में ज्ञानवापी नाम का ढांचा खड़ा है। औरंगजेब के वक्त में शासकीय आज्ञा से विश्वनाथ मंदिर को गिरा कर इस ढांचे का निर्माण किया गया था। मंदिर का कुछ हिस्सा ही सुरक्षित रहा था। ज्ञानवापी की दीवारें ही चिल्ला कर कह रही हैं कि वहां मंदिर था। कई दशकों से काशी के लोग काशी विश्वनाथ मंदिर को उसके मौलिक रूप में स्थापित करने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे।

न्यायालय ने आर्कियोलॉजी सर्वे आफ इंडिया को आदेश दिया कि इस ज्ञानवापी ढांचे के एक हिस्से का सर्वेक्षण किया जाए। सर्वेक्षण में पता चला कि ढांचे के अंदर और बाहर काफी सामान है जो यह सिद्ध करता है कि विश्वनाथ मंदिर को ही तोड़ा गया था। न्यायालय ने पर्याप्त प्रमाण देखकर तहखाने में, जहां 1993 तक पूजा होती थी, पूजा करने की अनुमति भी दे दी। इससे एटीएम अशरफ आग बबूला हो रहा है। जमीयत उलेमा–ए–हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि ऐसे फैसले लेने से बेहतर है कि देश में से कानून की सब किताबें ही जला दो। उन्होंने और भी आगे जाते हुए कहा कि इससे देश में दंगे शुरू हो जाएंगे। वैसे तो जमीयत उलेमा–ए–हिंद का भी आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की तरह भारत के देसी मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। यह भी एक अशरफ क्लब ही है। कानून की किताबों को जलाने की मौलाना अरशद मदनी की इच्छा समझ में आती है। भारत का अशरफ क्लब अभी भी मध्ययुगीन मुगलों की सत्ता की छाया से बाहर नहीं निकल पा रहा है। यदि भारत में अभी भी औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या बाबर की सत्ता होती तो मदनी और उसके लोग जरूर कानून की किताबों को जला देते। आखिर औरंगजेब ने भी विश्वनाथ का मंदिर कानून की किताबों को जलाकर ही तोड़ा होगा। अब कानून की किताबें उस मंदिर को दोबारा बनाने का रास्ता साफ कर रही हैं तो मदनी उन किताबों को ही एक बार फिर जलाने का सपना देख रहा है। मदनी जैसे लोग ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर हकलान हो रहे हैं। यह विश्वविद्यालय 1857 की आजादी की लड़ाई के बाद सैयदों ने खोला था। मकसद अशरफ मुसलमानों को अंग्रेजी सरकार के पक्ष में करना था। सैयदों को लगता था कि मुगल इस देश पर कब्जा किए हुए थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनसे सत्ता छीन ली। जिन दिनों मुगल राज था उन दिनों सैयद उनको शरीयत पढ़ा पढ़ा कर भारतीयों का खून चूसते थे। लेकिन अंग्रेजों के आ जाने से वे दर–बदर हो गए हैं। अंग्रेज तो फिर भी भाई हैं। 'पीपुल्स आफ दी बुक'। लेकिन देसी मुसलमान भी अंग्रेज के खिलाफ हो रहा है और अपने दूसरे भाई बंधुओं के साथ मिल कर अंग्रेजों को गालियां दे रहा है। यह देसी अलजाफ , अरजाल और पसमांदा मुसलमान हाथ से निकल गया तो सैयद अशरफ क्या घास खोदेंगे? इनको राह पर लाना के लिए इल्म का यह बड़ा मदरसा खोला गया। और यहां से ऐसी तालीम दी गई, जिसने देश का ही बंटवारा कर दिया। हद तो तब हो गई जब मुगलों व अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी अशरफ जिद कर रहे हैं कि इस 'दानिशगाह' को मुसलमानों की दानिशगाह मान लिया जाए। इसमें एससी के छात्रों के लिए आरक्षण न रखा जाए। विश्वविद्यालय का खर्चा सरकार उठाए और नियंत्रण एटीएम अशरफ का रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। उसका कहना था कि यह सरकारी विश्वविद्यालय है, इसलिए वैधानिक नियमों के अनुसार दाखिले में भी, और नौकरी में भी एससी को आरक्षण देना पड़ेगा। तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर संसद में कानून ही बदल दिया। अलीगढ़ का यह बड़ा मदरसा मुसलमानों के कब्जे में ही रहेगा। शब्द मुसलमान प्रयोग किया गया था, लेकिन व्यावहारिक रूप में उसका अर्थ अशरफ यानी एटीएम मुसलमान से ही था। अब मदनी जैसे पता नहीं कितने अशरफ कानून की किताबों को जला देने की बातें करने लगे हैं। देसी मुसलमान मुंह बाए देख रहा है।

सरकार प्रभावी होने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर

विनोद

उच्च विकास जनता में उपहार के रूप में दिखने की अनिच्छा पैदा करता है। जब विकास वैश्विक स्तर से दोगुने से अधिक हो और किसी भी तुलनित्र इकाई द्वारा प्राप्त उच्चतम हो, तो विवाद और भी कम होते हैं। यह स्टार्टअप और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए सच है। दोनों अनिश्चित भविष्य के बारे में "विश्लेषक धुंध" के अधीन हैं जो एक बहुत ही उज्ज्वल वर्तमान पर एक विश्लेषणात्मक प्रीमियम डालता है। भारत के लिए वर्तमान बेहद उज्ज्वल दिख रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में वास्तविक रूप से 7.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो कि वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि है। आईएमएफ ने अपने जनवरी 2024 के आकलन में अक्टूबर 2023 के अनुमान को 6.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले वित्तीय वर्ष में आईएमएफ की तुलना में सात प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जिसका अनुमान 6.5 प्रतिशत है। बाकी दुनिया उतनी चमकीली नहीं चमकती। आईएमएफ का आकलन है कि 2023 के दौरान उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि होगी, 2024 में अनुमानित वृद्धि 4.3 प्रतिशत और 2025 में 4.1 प्रतिशत होगी। इससे भारत अगले वित्त वर्ष (2024–25) में भी चीन से आगे सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। , जिसके 2023 में 5.2 प्रतिशत से घटकर 2024 में 4.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025–26 तक भी भारत की आर्थिक संभावनाओं पर एक निर्णायक सहमति है, जब आईएमएफ ने भारत के लिए 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है दृ वित्त वर्ष 2024–25 की तुलना में सावधानीपूर्वक कम– लेकिन फिर भी 2025 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए अनुमानित वृद्धि 4.2 प्रतिशत और चीन की 4.1 प्रतिशत से काफी आगे है। तो, क्या यह "अमृत काल" (प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का स्वर्णिम काल के लिए उपनाम) जैसा दिखता है? सच कहें तो, भारत का लंबे समय (दशकीय) अवधि में 6. 5 प्रतिशत से 6.7 प्रतिशत के बीच प्रदर्शन करने का इतिहास रहा है। विकास दर में 0.5 से एक प्रतिशत अंक के बीच बढ़ोतरी की कल्पना की जा सकती है। तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल अर्थव्यवस्था की गहरी पैठ से उत्पादकता में वृद्धि, वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में गिरावट और वैश्विक व्यापार रुझानों में मजबूती के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बढ़ा हुआ उपयोग विकास को गति दे सकता है। हालाँकि, ये सभी अनिश्चित, बहिर्जात घटनाओं पर आधारित काल्पनिक परिणाम बने हुए हैं। मायने यह रखता है कि हम यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि विकास धीमा न हो। सबसे आगे रहने के लिए एक स्मार्ट राष्ट्रीय रणनीति तीन स्तंभों के आधार पर तैयार की जा सकती है। सबसे पहले, हमने जो अच्छा किया है उसे जारी रखें। इसमें प्रतिबंधों से घिरे रूस से तेल जैसे वैश्विक सौदेबाजी या संभावित बड़े घरेलू बाजार के साथ मित्रवत तटों पर स्थानांतरित होने वाले हाई–टेक निवेश की तलाश शामिल है। पुनर्वासकर्ता उच्च विकास लेकिन तरजीही व्यवहार को और भी अधिक पसंद करते हैं दृ इसलिए सौदों पर बातचीत में लचीलापन महत्वपूर्ण है और राजनीतिक स्थिरता का आश्वासन भी महत्वपूर्ण है दृ बाद वाले को दिया हुआ माना जाता है। दूसरा, सभी निम्न–मध्यम अर्थव्यवस्था सरकारों के लिए लोक कल्याण केंद्रीय है। लेकिन जब कल्याणकारी हैंडआउट्स उत्पादकता वृद्धि में कम निवेश करके विकास से समझौता करते हैं तो एक लाल रेखा अवश्य खींची जानी चाहिए। बजट से भुगतान की जाने वाली राष्ट्रीय सब्सिडी वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 प्रतिशत यानी 4 ट्रिलियन रुपये है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से कर संग्रह में समानता में सुधार हुआ है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में कर के दायरे को बढ़ाना अभी भी प्रगति पर है। कर–से–जीडीपी अनुपात निम्न 9.98 प्रतिशत (2009) और उच्च 11. 17 प्रतिशत (2024) के बीच सीमित रहता है। सीमित राजस्व सार्वजनिक निवेश में बाधा डालता है। केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया गया 26 ट्रिलियन रुपये (+313 बिलियन) का शुद्ध कर "बड़ी सरकार" की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है दृ विनिर्माण में सीधे हस्तक्षेप, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, और किफायती घरों, अस्पतालों जैसी नई सार्वजनिक सुविधाएं जैसे निजी पूंजीगत सामान प्रदान करना। , स्कूल और कॉलेज। राजस्व प्राप्तियाँ सकल घरेलू उत्पाद के दो से तीन प्रतिशत तक बढ़नी चाहिए दृ या तो अधिक कर एकत्र करके या निर्मित सार्वजनिक संपत्तियों का मुद्रीकरण करके और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और बैंकों का निजीकरण करके पर्याप्त "अन्य गैर–कर राजस्व" उत्पन्न करके। अंतरिम बजट में इस मद में सब्सिडी पर खर्च के बराबर मात्र 4.1 ट्रिलियन रुपये (जीडीपी का 1.2 प्रतिशत) का लक्ष्य रखा गया है।

प्राप्तियों को व्यय की ठोस मांगों से जोड़ने से संभवतः आक्रामकता बढ़ सकती है।

कल्याणकारी सब्सिडी भुगतान और विकास सब्सिडी जैसे एमएसएमई के लिए सब्सिडी, हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी और ग्रिड के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण, परिवहन के विद्युतीकरण और हाई–टेक विनिर्माण पर बजटीय परिव्यय के लिए "अन्य पूंजीगत प्राप्तियों" को जोड़ने से न्यूनतम पैमाने और दायरे का निर्धारण किया जा सकता है। यह उपेक्षित राजस्व स्रोत है। 2022–23 से पूंजी परिव्यय में 50 प्रतिशत की वृद्धि (4.5 ट्रिलियन रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 प्रतिशत) के साथ हम पूंजी आवश्यकताओं और राजस्व अंतर दोनों को कवर करने के लिए स्थायी रूप से "उधार" लेने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।

यात्री सुविधाओं व रेल आय अर्जन में श्रेष्ठ प्रदर्शन से दिन प्रतिदिन नए कीर्तिमान रच रहा है

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। विशिष्ट रेलसेवा महाप्रबंधक पुरस्कार में लखनऊ मंडल के वाणिज्य विभागको, आरक्षण, केटरिंग एवं टिकट चेकिंग के लिए दक्षता शील्ड, व स्वच्छता की प्रथम शील्ड के लिए जौनपुर के वाणिज्य कर्मचारियों ने आरक्षण कार्यालय में मिठाई बांटकर खुशी मनाई । शनिवार को जौनपुर आरक्षण कार्यालय में आयोजित बैठक में वाणिज्य निरीक्षक सुल्तानपुर नीरज सोमवंशी ने बताया कि उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वाणिज्य विभाग का पूरे जोन में यात्री सुविधाओं व रेल आय अर्जन में श्रेष्ठ प्रदर्शन से दिन प्रतिदिन नए कीर्तिमान रच रहा है।

मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक जौनपुर सिटी अनुराग तिवारी ने लखनऊ मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु,कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ बरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्रीमती रेखा शर्मा जी को आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया।

बैठक में आरक्षण पर्यवेक्षक परमेश्वर यादव ने कहा रेल की छवि और विश्वनीयता दोनों में बृद्धि नए कलेवर के कार्यप्रणाली के कारण ही सम्भव हुआ है। अंत में मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक जौनपुर जंक्शन सुनील कुमार मिश्र द्वारा वाणिज्य विभाग के यात्री सुविधा के हर क्षेत्र श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मिठाई बांटी गई और उपस्थित कर्मचारियों को आभार व्यक्त किया गया।

बैठक में संतोष कुमारी, सुमन यादव, रेनू सिंह, पन्नालाल यादव, शाखामंत्री यू आर एम यू राकेश सिंह, बृजेश विश्वकर्मा, अमित प्रसाद, शालिनी यादव, ओमप्रकाश यादव जितेंद्र कुमार आदि रेलकर्मी उपस्थिति रहे।

सात दिवसीय एनएसएस कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। शाहगंज, नगर क्षेत्र स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित करके महाविद्यालय के प्रोफेसर और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डाक्टर मोती चंद द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर डाक्टर अखिलेश ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहा करते थे तब तक मत रूको जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुँच जाओ। राष्ट्र सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। यही मूलमंत्र राष्ट्रीय सेवा योजना का भी है। कार्यक्रम अधिकारी डाक्टर रमेश चंद्र ने छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में देश के प्रति समर्पण की भावना का विकास करना तथा हर प्रस्थिति में अपने आपको देश के लिए तैयार रखना है। देश सेवा के बहुत सारी ईकाईयां हैं उन्ही में से एक एक ईकाई राष्ट्रीय सेवा योजना की भी है। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा विविध प्रकार के सास्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गयी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डाक्टर पुजा गुप्ता, डाक्टर रमेश चंद्र, डाक्टर मोती चंद,सभी अध्यापक अध्यापिकाएं सहित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी गण उपस्थित रहें।

ट्रैक्टर एजेंसी पर खड़ी बोलेरो चोरों ने उड़ाया

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। खुटहन थाना अंतर्गत चौराहे के बगल पिलकिछा मार्ग पर बजरंग ट्रैक्टर एजेंसी पर खड़ी बोलेरो गाड़ी शुक्रवार की रात चोरों ने उड़ा दिया। जिसकी जानकारी एजेंसी संचालक को दूसरे दिन सुबह हुई। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस एजेंसी व अन्य प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी का फुटेज खंगाल रही है। एजेंसी संचालक काजीशाहपुर गांव निवासी प्रेमचंद्र यादव का आरोप है कि शुक्रवार को सरपतहा थाना क्षेत्र के चौबाहा भगासा गांव निवासी संतोष कुमार तिवारी ने एजेंसी से नया ट्रैक्टर खरीदा था। समझौते के तहत उसने बदले में पैसा न देकर अपनी बोलेरो गाड़ी प्रेमचंद्र को देकर ट्रैक्टर अपने घर ले गया। रोज की तरह रात लगभग दस बजे एजेंसी का सटर बंद कर सभी कर्मचारी अपने घर चले गए। रात में अज्ञात चोरों ने बाहर खड़े वाहन को निशाना बना दिया।

सामाजिक-आर्थिक सांस्कृतिक बदलाव के अध्ययन के लिए शोध जरूरी - डा. माणिक कुमार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के संकाय भवन के संगोष्ठी हाल में शनिवार

को दो सप्ताह का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में प्रबंध संकाय के पूर्व संकायाध्यक्ष प्रो. अविनाश पाथर्डीकर ने प्रथम सत्र में सहसंबंध, रिग्रेशन एनालिसिस, उसके अपवाद व उपयोगिता पर प्रतिभागियों को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि सहसंबंध अनुसंधान दो चरों के बीच संबंध का एक सांख्यिकीय माप है। इसमें एक शोधकर्ता दो चर को मापता है, किसी भी बाहरी चर के प्रभाव के बिना उनके बीच सांख्यिकीय संबंध को समझते हुये उसका आकलन करता है और यह निर्धारित करता हैं कि वे सहसंबद्ध हैं या नहीं । इसको अमेरिका में हुए आइसक्रीम, अपराध बढ़ोतरी पर हुए उदाहरण के साथ समझाते हुए इसकी व्याहारिक पहलू पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों को अलर्ट भी किया । कार्यशाला के द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज से आये डॉ माणिक कुमार ने कहा कि समाज–देश–विश्व में हो रहे सामाजिक–आर्थिक सांस्कृतिक बदलाव के अध्ययन के लिए शोध जरूरी है। इसके लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट व राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के स्ट्रेटा, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बेरोजगारी, रोजगार इत्यादि अवयवों का अवलोकन करना सिखाया। प्राध्यापक–शोधार्थी को इस प्रकार के शोध के जरिए समस्या निवारण का प्रयास कर सकता है। सामाजिक शोध में आने वाली समस्याओं बारे भी डॉ कुमार ने चर्चा की। इस पर प्रो. अजय प्रताप सिंह, डॉ मनोज पांडेय, डॉ. जाह्नवी श्रीवास्तव, डॉ. अनु त्यागी, अनुपम आदि ने भाग लिया।

फीनिक्स पलासियो में इस लव सीजन हो रही हैं बेहद रोमांटिक एक्जिविटीज, साथ ही शापिंग आफर्स में कुछ खास पाने का मौका

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। लखनऊ का फेवरिट शॉपिंग और लीजर एक्टिविटीज सेंटर बन चुका फीनिक्स पलासियो अपने शॉपर्स के लिए वेलेंटाइन डे पर खास आयोजन कर रहा है। प्यार का मौसम दस्तक दे चुका है और प्यार का इजहार करने के लिए इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है? तो तैयार हो जाइए, फीनिक्स पैलेसियो के ष्सेलिब्रेट लवष कैंपेन के साथ प्यार के जादू में खो जाने के लिए। इस कैंपेन में शानदार सजावट, इंटरैक्टिव गतिविधियाँ और आकर्षक पुरस्कार शामिल हैं, जो निश्चित रूप से आपके दिल को छू लेंगे। प्यार के इस मौसम मेंअपने प्यार का इजहार करने का इससे अच्छा वक्त और क्या हो सकता है? फीनिक्स पलासियो में सेलिब्रेट लव के साथ प्यार के जादू में खो जाइए, जहां आपको इंटरैक्टिव गतिविधियां, आकर्षक पुरस्कार और दिल को मोह लेने वाली सजावट देखने को मिलेंगी। मॉल में बनाया गया ष्मेसेज ऑफ द हार्ट एक ऐसा इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन है जिसे प्यार को साझा करने, गेम खेलने और लंबे समय तक रहने वाली यादें देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस इंस्टॉलेशन में अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए एक पूरी आकर्षक श्रृंखला है, जिसमें ष्मेसेज इन ए बॉटल स्टेशनष भी शामिल है। खरीदार अपने प्रियजनों के लिए अपने दिल की भावनाओं को संदेश के रूप में लिख सकते हैं, अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न सजावटी सामग्रियों का उपयोग करके इसे पर्सनल टच दे सकते हैं और इस बोतल को सजा सकते हैं। अपने प्यार भरे संदेश को आकर्षक तरीके से, इस इंस्टालेशन में बने एक विशाल दिल से लटका सकते हैं। आपके प्रियजन आपके द्वारा लिखे गए मेसेज वाली इन बोतलों को मोमेंटो के रूप में अपने साथ ले जा सकते हैं। इसी तरह क्यूपिड्स ऐरो गेम आपके लिए एक रोमांचक अनुभव लेकर आया है, जो प्रियतम को प्यार का निशाना बनाने का मौका देता है। इसमें आपको प्यार के देवता क्यूपिड का धनुष उठाकर सामने बने दिलों पर निशाना लगाना है। यदि तीर निशाने पर लगते हैं तो आपको हर सही निशाने के लिए अंक मिलेंगे। इनके बदले आप बेहतरीन पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके प्रियतम को देने या किसी खास से प्यार व्यक्त करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। इसके अलावा सदा के लिए यादें संजोने के लिए एक बड़े आकार के ग्लोइंग फोटोजेनिक लव साइन के साथ फोटोग्राफ्स क्लिक करें। यह साइन आपकी तस्वीरों के लिए एकदम सही बैकड्रॉप प्रदान करेगा। इन फोटोग्राफ्स को आप अपने पसंदीदा हैशटैग्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं। इन गतिविधियों में शामिल होने के बाद, आपको अपने प्रियजनों के लिए खरीदारी करने और विशेष पुरस्कार जीतने का अवसर भी है। तो आइए और प्यार के इस मौसम में करें कुछ प्यार भरी खरीदारी। रू0,000 या इससे अधिक की खरीदारी कर आप उन 30 भाग्यशाली जोड़ों में शामिल हो सकते हैं, जिन्हे हेलीकॉप्टर राइड का शानदार मौका मिलेगा। साथ ही रू15,000 की खरीदारी करने पर आपको अपने प्रियजनों को देने के लिए एक सुनिश्चित उपहार भी मिलेगा। फीनिक्स मिल्स के सीनियर सेंटर डायरेक्टर श्री संजीव सरीन ने कहा, हम इस वैलेंटाइन्स डे को आपके लिए खास बनाना चाहते हैं। प्यार के इस मौसम में, हम अपने शॉपर्स के लिए सेलिब्रेट लव कैंपेन लेकर आए हैं, जो आपको अपने प्रियजनों के साथ एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करने का अवसर दे रहा है। साथ ही इस दौरान आप शॉपिंग कर निश्चित उपहार जीतने और हेलीकॉप्टर राइड पर जाने का शानदार मौका पा सकते हैं।

कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने किया रक्तदान शिविर का शुभारम्भ

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। हरिओम सेवा केंद्र तथा सिविल अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में लखनऊ विश्व विद्यालय मे रक्तदान शिविर का आयोजन आरोग्य भवन में किया गया। शिविर का शुभारम्भ तथा उत्साहवर्धन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या मे छात्र छात्राओं ने भाग लिया एवं स्वयैछिक रक्तदान किया। शिविर का आयोजन अधिस्ताता छात्र कल्याण प्रोफेसर संगीता साहू के निर्देशन मे आरोग्य भवन इंचार्ज डा कुसुम यादव द्वारा किया गया। इस

अवसर पर डीन अकादमी प्रोफेसर गीतांजली मिश्र, हरिओम सेवा केंद्र के संस्थापक तथा प्रसिद्ध थियेटर कर्मी डा अनिल रस्तोगी सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने रात्रि कालीन सफाई अभियान का झाड़ू लगाकर किया शुभारंभ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉदड़ के द्वारा शुक्रवार देर रात रात्रिकालीन सफाई अभियान की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी ने चहारसू चौराहे पर झाड़ू लगाकर सफाई/स्वच्छता अभियान की शुरुआत किया। उन्होंने बताया कि नियमित रूप से रात में सफाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने रोडवेज परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर, ओलन्दगंज, सद्भावना पुल, चहारसू चौराहा, रेलवे स्टेशनो, सब्जी मंडी सहित नगर के प्रमुख चौराहों एवं अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर नियमित रूप से साफ–सफाई के निर्देश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जौनपुर पवन कुमार को दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य है कि व्यापारियों, आमजन को अच्छी सुविधाएं मिले, गंदगी से निजात मिले, नगर पालिका व ग्राम पंचायत में साफ–सफाई रहेगी तो बीमारियों का प्रसार भी कम होगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से भी अपील किया है कि सफाई को अपने दिनचर्या में शामिल करें और जनपद को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग प्रदान करें, साफ–सफाई हम सबकी जिम्मेदारी है, सभी को श्रम दान करने को भी कहा।

रात्रि कालीन सफाई के लिए 40 सफाई कर्मी, 2 सेनेटरी इंस्पेक्टर और 2 सुपरवाइजर लगाए गए है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पवन कुमार, सेनेटरी इंस्पेक्टर, सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

गोएल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड साइंसेस में नव प्रवेशित छात्रों का आगमन

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। गोयल ग्रुप ऑफ इंस्टीटूशंस के गोयलप्लेक्स हॉल में गोएल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड साइंसेस (जीआईपीएस) के बैचलर एवं डिप्लोमा फार्मेसी में नव प्रवेशित छात्र–छात्राओं के स्वागत के लिए हर्षोल्लास के साथ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन ष्आगमनष के रूप में किया गया। बतौर मुख्य अतिथि रेडियो मिर्ची से आर.जे. आलोक कार्यक्रम की शोभा के रूप में उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान गोयल ग्रुप के प्रबंध निदेशक, इंजी. महेश गोएल, निदेशक (समन्वय और योजना) डॉ. अलोक जैन और जीआईपीएस निदेशक, डॉ. ओपी वर्मा के साथ अन्य सम्मानित निदेशकों एवं शिक्षकों ने इस समारोह में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सभी छात्र एवं छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की वंदना से हुई। छात्रों ने नाटक, नृत्य, और संगीतीय प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन उत्साहपूर्वक किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान मिस्टर एवं मिस फ्रेशर का चुनाव केंद्र बिंदु रहा जिसको जानने की जिज्ञासा ने सभी को कार्यक्रम के अन्त तक बाँधे रखा। छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार की

रचनात्मकतापूर्ण और मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित सभी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. ओपी वर्मा ने दीप प्रज्ज्वलन एवं स्वागत भाषण से किया। डॉ. ओपी वर्मा ने अतिथिओं का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर किया और साथ ही साथ उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए सभी उपस्थित लोगों का आभार भी व्यक्त किया। दिन ढलने के साथ ही कार्यक्रम के अंतिम पलों में मिस्टर एवं मिस फ्रेशर नाम जानने के साथ ही लोगों की जिज्ञासा का अंत हुआ। बैचलर फार्मेसी में निखलेश एवं श्रद्धा तथा डिप्लोमा फार्मेसी में रोहन एवं मधू का चुनाव मिस्टर फ्रेशर एवं मिस फ्रेशर के रूप में हुआ। कार्यक्रम का समापन डॉ. ओपी वर्मा एवं अन्य गणमान्य शिक्षकों द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के पश्चात् सभी विद्यार्थियों को भविष्य के लिए शुभकामना संदेश देने के साथ हुआ। जीआईपीएस के नए छात्रों के लिए, यह महोत्सव सिर्फ एक उत्सव भर ही नहीं है बल्कि यह उनकी शैक्षिक यात्रा की शुरुआत है,

जिसमें सहयोग, साझेदारी, और संवाद के महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया गया। नए छात्रों के लिए, इस महोत्सव के साथ जुड़ी यादें और अनुभव उन्हें उनके अध्ययन के लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करेंगी।

मेडिकल टेक्नोलॉजी में अपोलोमेडिक्स हास्पिटल की उल्लेखनीय उपलब्धि, एआई आधारित 3डी प्रिंटिंग से बनाया मरीज का जबड़ा

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। उल्लेखनीय चिकित्सा उपलब्धि हासिल करते हुए लखनऊ के अपोलोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और 3डी प्रिंटिंग का उपयोग करके अमेलोब्लास्टोमा मैंडिबल नामक जबड़े के ट्यूमर का सफल इलाज किया है। इस इलाज में डॉक्टरों ने न केवल जबड़े के ट्यूमर का सफल इलाज किया बल्कि जबड़े का पुनर्निर्माण भी कर दिया। 50 वर्षीय मरीज इस सफल सर्जरी के बाद सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है। इस सर्जरी प्रक्रिया का लखनऊ और आसपास के क्षेत्र में पहली बार उपयोग किया गया। मरीज जबड़े में दर्द और खाने में होने वाली असुविधा की शिकायत के साथ अपोलोमेडिक्स अस्पताल की ओपीडी पहुंचा था। गहन जांच और स्कैन के बाद, इलाज के लिए सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में सलाहकार डॉ. सतीश के आनंदन के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने जबड़े और जोड़ के पूरे बाएं हिस्से को हटाने की आवश्यकता बताई। इतना बड़ा और जरूरी हिस्सा चेहरे से हटाने की बात पर मरीज को इस बात की चिंता थी कि क्या वो ठीक से खा–पी पाएगा और उसका चेहरा कैसा दिखेगा? अस्पताल में डॉक्टर्स के पैनल ने विचार विमर्श के बाद डॉ. सतीश के आनंदन द्वारा ट्यूमर को हटाने और फिर जबड़े के पुनर्निर्माण का जटिल प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय लिया। प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कंसल्टेंट डॉ. निखिल पुरी और एसोसिएट कंसल्टेंट डॉ. आशीष विलास उके

ने इस रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जबड़े को वापस सामान्य स्थिति में लाया गया। प्लास्टिक सर्जरी टीम ने मरीज और उसके परिवार से जबड़े की हड्डी के पुनर्निर्माण के बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि कैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 3डी प्रिंटेड इम्प्लांट का इस्तेमाल करके हड्डी को फिर से बनाया जा सकता है। यह इम्प्लांट पूरी तरह से मरीज के हिसाब से बनाया गया था, ताकि यह हटाए गए हिस्से की एकदम सटीक प्रतिकृति हो सके। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी टीम ने यह तय किया कि हड्डी को कहां से काटा जाएगा। इसके बाद, प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी टीम ने कंप्यूटर की मदद से एक नया जबड़ा बनाया। यह नया जबड़ा हटाए गए जबड़े के आकार और आकार से बिल्कुल मेल खाता था। पूरी सर्जरी की योजना कंप्यूटर की मदद से बनाई गई थी। ऑपरेशन के दौरान, डॉक्टरों ने इस योजना का बिल्कुल सटीक ढंग से पालन किया। पूरी प्रक्रिया में लगभग एक महीने का समय लगा। सर्जरी सफल रही और अब मरीज दर्द से मुक्त है। वह अब सामान्य रूप से खा और बोल सकता है। उसके चेहरे का आकार भी सामान्य हो गया है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में कंसल्टेंट डॉ. सतीश के आनंदन ने जबड़े के ट्यूमर की जटिल सर्जरी पर अनुभव साझा करते हुए बताया, ष्अमेलोब्लास्टोमा मेम्बिबल ने एक अनोखी चुनौती पेश की, जिसे सावधानीपूर्वक हटाने की आवश्यकता थी। हमारा ध्यान सिर्फ ट्यूमर के इलाज पर नहीं था बल्कि सर्जरी के बाद मरीज के जबड़े की सामान्य संरचनाओं और उसकी कार्यक्षमता सुनिश्चित करना भी था। प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में कंसल्टेंट डॉ. निखिल पुरी ने कहा, ष्हमारा ध्यान सिर्फ ट्यूमर को हटाना ही नहीं था, बल्कि सर्जरी के बाद मरीज के जबड़े की हड्डी को पहले जैसा काम करने लायक बनाना भी था। एआई आधारित 3डी प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। यह हमें ट्रांसप्लांट को कस्टम–डिजाइन करने की सुविधा देता है, जिससे मरीज के लिए एकदम सटीक अंग का पुनर्निर्माण संभव होता है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती–2023 के पदों पर आयोजित होने वाली परीक्षा के सम्बन्ध में की गयी ब्रीफिंग

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 10.02.2024 को पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग सभागार में अध्यक्ष/पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के साथ उ0प्र0 पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस–2023 सीधी भर्ती के पदों पर दिनॉकः 17.02.2024 व 18.02.2024 को आयोजित होने वाली परीक्षा के सम्बन्ध में समस्त जनपद ध पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद के सहायक नोडल अधिकारियों (अपर पुलिस अधीक्षकध्अपर पुलिस उपायुक्त) की ब्रीफिंग कर महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निम्नांकित निर्देश दिये गये –

परीक्षा की तिथि को जनपद/कमिश्नरेट में कुल परीक्षार्थियों की संख्या का आकलन कर तद्नुसार प्रभावी यातायात ध सुरक्षाध्पुलिस प्रबन्ध किया जाए। महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट पर क्यूआरटी टीमों का व्यवस्थापन किया जाये। परीक्षा केन्द्र पर उत्कृष्ट व्यवस्थापन व प्रबन्धन हेतु जिलाधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ उत्कृष्ट समन्वय स्थापित कर समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। परीक्षा केन्द्रों तथा रेलवे/मेट्रो स्टेशन एवं बस/टैक्सी स्टैण्ड तथा होटल/रेस्टोरेन्ट पर भीड़ प्रबन्धन हेतु कार्ययोजना बनाकर व्यवस्थापन किया जाये। राजपत्रित अधिकारियों एवं मजिस्ट्रेट की संयुक्त रूप से ड्यूटी लगायी जाये। महिला परीक्षार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाये। जनपदीय अभिसूचना तंत्र व सोशल मीडिया सेल को और अधिक सकिय व सर्तक कर दिया जाय। परीक्षा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अफवाह या आपत्ति जनक तथ्यों का तत्काल संज्ञान लेकर उसका खण्डन करते हुये विधिक कार्यवाही की जाये। विभिन्न होटलों/धर्मशालाओं/पार्को/बस स्टाप एवं रेलवे स्टेशनों पर परीक्षार्थियों के आवागमन के दृष्टिगत प्रभावी पुलिस प्रबन्ध व पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाये। उक्त परीक्षा के सम्बन्ध में नियमित तिथि एवं समय पर सुदृढ़ व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी के माध्यम से आयोजकों ध विभिन्न राजकीय विभागों ध रेलवे आदि से भी समन्वय स्थापित कर अपेक्षानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में पुरूष ध महिला पुलिस बल की व्यवस्था तथा प्रश्नपत्रों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुँचाने एवं उत्तर पुस्तिकाओं की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड अपर पुलिस महानिदेशक एसटीएफ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए मेदांता अस्पताल ने आयोजित किया प्रेरणादायी संवाद रूबरू

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर, मेदांता अस्पताल, लखनऊ ने संवाद कार्यक्रम रूबरू का आयोजन किया। इसका उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कैंसर पीड़ितों का मनोबल बढ़ाना था। कार्यक्रम में कैंसर पीड़ितों के अदम्य साहस को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद, विभिन्न वक्ताओं ने कैंसर के बारे में जानकारी दी और कैंसर रोगियों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को कैंसर सर्वाइवर्स के प्रेरक अनुभव सुनने का अवसर मिला। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे उन्हें कैंसर का पता चला, इलाज के दौरान उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इलाज के बाद भी किन परेशानियों से जूझना पड़ा। यह चर्चा कैंसर के मरीजों और उनके परिवारों के लिए प्रेरणा और उम्मीद का स्रोत बन गया। कार्यक्रम में मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने रोगियों, उनके परिवारों और समुदायों पर कैंसर के गहरे प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ष्रूबरूष पहल का उपयोग करके सकारात्मका का प्रसार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर मेदांता अस्पताल, लखनऊ के मेडिकल डायरेक्टर डॉ राकेश कपूर ने कहा, ष्मेदांता अस्पताल लखनऊ ने कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे कई रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। अपने प्रयासों को विस्तारित करके, हम कैंसर से प्रभावित लोगों की इलाज की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए समर्पित हैं।

मछुआरों को वितरित किया गया नाव व मछली पकड़ने का उपकरण

(डॉ अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। शनिवार को प्रदेश सरकार द्वारा निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के तहत मछुवारों को नाव सहित मछली पकड़ने के उपकरण वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में 18 मछुवारों को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में पहुंचे उप निर्देशक मत्स्य राजेंद्र सिंह विष्ट द्वारा नाव सहित अन्य सामग्रियों का वितरण हुआ। इस मौके पर उपनिदेशक मत्स्य राजेंद्र सिंह ने बताया कि निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत 18 नांव का वितरण किया गया है, ।जिसमें एक नाव,एक आइस बॉक्स, एक जाल व लाइफ जैकेट मौजूद थे। उन्होंने बताया कि यह योजना प्रदेश सरकार की यह एक महत्वपूर्ण योजना है,जो हमारे मछुआरे हैं उनके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी।उन्होंने बताया कि अब तक यह लोग नाव खरीदते थे, बेचते थे और शासन की तरफ से इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। सरकार इन लोगों को सुविधा उपलब्ध करा रही है, जिससे ये सभी मछुआरा समाज के लोग बेहतर ढंग से जीवन यापन कर सकें। इस योजना के तहत 87 नांव वितरण करने का लक्ष्य था,18 नाव दी जा रही है, और आगे भी दिया जाएगा।इस मौके पर क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य पिछड़ा मोर्चा श्याम लाल निषाद, जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी संगठन डॉ विजय कुमार निषाद, रवि सोनकर निवर्तमान वर्तमान मंडल अध्यक्ष,जितेंद्र निषाद पार्षद, राम आशीष निषाद, हेमंत निषाद, अरविन्द निषाद के अलावा मछुआ समाज के लोग मौजूद रहे।

भारतीय एकता समिति ने किया सर्द मौसम में गरम कपड़ों का वितरण

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। भारतीय एकता समिति एक सामाजिक,सांस्कृतिक संस्था है जो निरन्तर विगत कई वर्षों से सामाजिक एव सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य कर रही है।इसी क्रम में समिति के पदाधिकारियों ने जरूरतमंदो, अहसाय व्यक्तियों को किया गरम कपड़ों का वितरण समिति के अध्यक्ष रविन्द सिह बिश्ट ने कहा कि समिति सदैव सामाजिक क्षेत्रों में निरन्तर कार्य कर रही है यह भी समिति के कार्यो के एजेन्डे में है जो भी जनहित के कार्य है व करती रहेगी और समिति शीघ्र ही एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेगी। समिति के महासचिव हेमवंत सिह ने बताया संस्था हमेषा से जनजागरूकता व सामाजिक कार्य करती रही है जैसे टीकाकरण करना हो ,बल्ड डोनेशन, वृक्षारोण, स्वच्छता अभियान चलाना हो ,सामाजिक क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वालों का सम्मान ,भूतपूर्व सेनिको का सम्मान, खेल में अपनी प्रतिभावों का सम्मान सहित कई कार्य करती रहती है आगे भी निरन्तर इस तरह के कार्य जारी रहेगे।

जरूरतमंदों को गरम कपड़े वितरित करने में समिति के सदस्य गोपाल गैलाकोटी, हरपाल सिह गडिया, रमेष अधिकरी, अभिशेक वर्मा सहित कई सामाजिक कार्यकता उपस्थित रहें।

नकल मुक्त परीक्षा कराने के लिये जिले में कुल 116 परीक्षा केंद्र निर्धारित

32 मिल्कीपुर में सबसे अधिक तथा सबसे कम 18–18 रुदौली सोहावल तहसील में बने परीक्षा केंद्र

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। यूपी बोर्ड परीक्षा तैयारी को लेकर जहां एक ओर शिक्षा विभाग के कर्मचारी जहां एक ओर उत्तर पुस्तिकाओं सहित अन्य सामग्रियों को परीक्षा केंद्रों पर वितरण करने में लगे हुए हैं।वही जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात बोर्ड परीक्षा प्रभारी प्रदीप कुमार व उनकी टीम बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन व नकल माफिया से मुक्त करने के लिये परीक्षा केंद्रों पर कक्ष निरीक्षकों की सूची बनाने में जुटे हुए थे।उन्होंने बताया कि इस बार हाई स्कूल व इंटर बोर्ड परीक्षा में कुल 116 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।जिसमें सबसे अधिक परीक्षा केंद्र मिल्कीपुर तहसील में बनाए गए हैं। यहां पर कुल 32 परीक्षा केंद्र बने हैं। वही सबसे कम परीक्षा केंद्र रुदौली व सोहावल तहसील में कुल 18–18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा जिले के बीकापुर तहसील में कुल 20,सदर तहसील व नगर क्षेत्र में कुल मिलाकर 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि परीक्षार्थियों की संख्या व मानक के मुताबिक इन परीक्षा केंद्रों पर कक्ष निरीक्षकों व केन्द्र व्यवस्थापक के साथ साथ सह केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती की जायेगी।उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सभी परीक्षा केंद्रों पर केन्द्र व्यवस्थापक,कक्ष निरीक्षक के साथ साथ सह कक्ष निरीक्षकों की तैनाती के लिये प्रारुप भेज दिया गया है।जो प्रारुप उनके माध्यम से जिले के सभी विकास खण्डों में तैनात खण्ड शिक्षा अधिकारी को भेज दी जाएगी।कुल मिलाकर बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर शिक्षा विभाग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है।

नौगजी मजार का तीन दिवसीय सालाना उर्स सम्पन्न

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। शहर के पीछे स्थित हजरत नूह अलैहस्सलाम (नौगजी मजार) जहां का उर्स –ए– मुकदस तीन दिवसीय सालाना उर्स धूमधाम से संपन्न हुआ। जिसमें भारी संख्या में हिंदू–मुस्लिम के लोग शामिल रहे।हजरत नूह अलैहस्सलाम नौगजी मजार का तीन दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत 7 फरवरी को कुल शरीफ और कुरआन खानी के कार्यक्रम से शुरु होकर नौ फरवरी तक चला। उर्स के दूसरे दिन 8 तारीख को कव्वाली का कार्यक्रम तथा 9 फरवरी को अंतिम दिन को तकरीर और नात–ए–मुशायरा का कार्यक्रम का आयोजन हुआ।जिसमें हिंदुस्तान हुआ के मशहूर मौलाना तशरीफ लाए नात–ए–मुशायरा के प्रोग्राम से कायर्क्रम में चार चांद लग गया और गागर और चादर का प्रोग्राम हुआ।चादर नवगजी मजार से निकल कर प्रमोदवन होते हुए अयोध्या कोतवाली के पीछे नौगजी मजार पहुँची जिसमे सैकड़ो महिलाएं एवं पुरुष सामिल हुए।कार्यक्रम में हाजी सईद,मो.कलीम सिद्दीकी,वसीम सिद्दीकी, मोहम्मद इम्तियाज ,नफीस अहमद खान ,सैफ खान ,सोहेब खान ,महताब खान, शिब्बू,इमरान अंसारी ,मो.नईम,आजम कादरी , मौलाना असलम, मौलाना अयूब ,रजा मोहम्मद ,अंकित,उमर,रिशु ,ललित ,गुड्डू ,सहित सैकड़ो लोग सामिल हुए ।

एसकेडी अकैडमी की विक्रांत खंड, गोमतीनगर शाखा में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल का आयोजन

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। एसकेडी अकैडमी की विक्रांत खंड, गोमतीनगर शाखा में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ एस के डी ग्रुप आफ एजुकेशन के निदेशक श्री मनीष सिंह ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। अपने आशीर्वचन में श्री मनीष सिंह ने छात्र–छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह स्कूली शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और इसके लिए सभी विद्यार्थियों को ईश्वर, माता–पिता और शिक्षकों के प्रति उन्हें कृतज्ञ होना चाहिए जिनकी कृपा और मार्गदर्शन से वह यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने सभी को परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने के साथ साथ उज्जवल भविष्य के लिए भी शुभकामनायें दी. इस अवसर पर आयोजित मिस्टर और मिस फेयरवेल स्टार प्रतियोगिता में मिस फेयरवेल स्टार और मिस्टर फेयरवेल स्टार का किताब क्रमशः वैष्णवी मिश्रा और मानस पांडे को मिला। इस अवसर पर समूह की उपनिदेशक श्रीमती निशा सिंह, सह– निदेशक श्रीमती कुसुम बत्रा, सह–निदेशक श्री डी के सिंह, एस के डी अकैडमी वृंदावन की प्रधानाचार्या डॉक्टर कविता श्रीवास्तव और सम्मानित शिक्षकगण उपस्थित थे।

सीएफओ एमपी सिंह ने न्यू टेंट सिटी का किया निरीक्षण

अयोध्या। शुक्रवार को सीएफओ एमपी सिंह ने अग्निशमन अधिकारी नागेन्द्र कुमार द्विवेदी के साथ न्यू टेंट सिटी का निरीक्षण किया।इस मौके पर वहां पर तैनात सभी फायर कर्मियों को सावधानी बरतने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।इस संबंध में अग्निशमन अधिकारी श्री द्विवेदी ने बताया सीएफओ एमपी सिंह ने खुद न्यू टेंट सिटी के अंदर बाहर की व्यवस्था को देखा कि वास्तव में न्यू इस टेंट सिटी का निर्माण अग्निशमन विभाग के मानक के अनुसार किया गया है कि नही।बताते चलें कि इस न्यू टेंट सिटी में अंजनेरी, चित्रकूट, पंचवटी, मिथिला, प्रयाग अतिथि व बाल्मीकि अतिथि गृह शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसकी सुरक्षा के लिए अंजनेरी और बाल्मीकि अतिथि गृह) पर दो फायर की गाड़ी पर्याप्त संख्या में फायर कर्मियों के साथ मौजूद हैं। जहां पर किसी भी अप्रिय स्थिति में निपटने के लिए फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की तैनाती की गई है।उन्होंने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में लोग सीएफओ एमपी सिंह के मोबाइल नंबर 9454418374, अग्निशमन अधिकारी नागेन्द्र कुमार द्विवेदी के मोबाइल नंबर 9454418708 तथा फायर स्टेशन पुलिस लाइन स्थित नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 9454418709 तत्काल सम्पर्क कर सकते हैं। जिससे किसी भी अग्निकांड पर समय रहते नियंत्रण किया जा सके।

स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप के साथ आईआईए नैटकॉन 2024 का हुआ शानदार शुभारंभ

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स (आईआईए) यूपी चौप्टर द्वारा आयोजित आईआईए नैटकॉन 2024 का आज लखनऊ में शानदार शुभारंभ हुआ। यह तीन दिवसीय मेगा आर्किटेक्चर इवेंट 9 से 11 फरवरी तक इकाना स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान आयोजित एग्जिबिशन में देश–विदेश की 60 कंपनियां अपने आर्किटेक्चर और बिल्डिंग से संबंधित उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। यह प्रदर्शनी 11 फरवरी तक सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी में सभी के लिए प्रवेश निशुल्क है। इवेंट के पहले दिन, उत्तर प्रदेश के माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री आशीष सिंह पटेल ने आर्किटेक्चर के छात्रों के लिए आयोजित होने वाली वर्कशॉप्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर, उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि वास्तुकला एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रचनात्मकता और तकनीकी कौशल का मेल होता है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे इस इवेंट का अधिकतम लाभ उठाएं और देश के प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट्स से सीखें। आज के कार्यक्रम में ओरिगेमी और बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग (बीआईएम) विषयों पर स्टूडेंट वर्कशॉप्स आयोजित की गईं। इन वर्कशॉप्स में, छात्रों ने वास्तुकला के विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्राप्त की। प्रसिद्ध वास्तुकार श्री आशीष सोमपुरा ने राम मंदिर निर्माण पर एक प्रेरणादायक प्रेजेंटेशन दिया। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार श्री आशीष सोमपुरा ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार राम मंदिर निर्माण पर अपना प्रेजेंटेशन दिया है। इस कार्यक्रम में एक बड़ी होम डेकोर एग्जिबिशन भी आयोजित की गई है, जिसमें 60 देश–विदेश की कंपनियां आर्किटेक्चर और बिल्डिंग से संबंधित अपने प्रोडक्ट्स प्रदर्शित कर रही हैं। इस तीन दिवसीय मेगा इवेंट में लगभग 2500 प्रतिनिधियों के भाग ले रहे हैं। इनमें से देश के अलग–अलग हिस्सों से 1500, उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से 500 आर्किटेक्ट्स और अलग–अलग आर्किटेक्चर कॉलेजों के 500 छात्र शामिल हैं। श्री संदीप कुमार सारस्वत, चेयरमैन आईआईए यू.पी. चौप्टर ने इस आयोजन के विषय में बात करते हुए कहा, आईआईए नैटकॉन 2024 न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में शहरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। आईआईए नैटकॉन 2024 का उद्देश्य संवर्धन थीम के तहत व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना है। हम न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में आर्किटेक्ट्स के बीच संवाद को बढ़ावा देकर भारत के निर्माण और बुनियादी ढांचे क्षेत्रों में चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं।

सवायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने शैक्षिक, ढांचागत और आर्थिक विकास हेतु विभिन्न प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपे

हरदोई (अंबरीष कुमार सक्सेना)

लखनऊ में आज मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आवास पर आयोजित लखनऊ मण्डल के विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों से भेंटवार्ता में सवायजपुर विधायक श्री माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने क्षेत्र के शैक्षिक, ढांचागत और आर्थिक विकास हेतु विभिन्न प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपे। जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए । इस दौरान सवायजपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न मार्गों के निर्माण, शासन में लम्बित हरपालपुर को नगर पंचायत बनाने की स्वीकृति, सवायजपुर क्षेत्र में एक डिग्री कालेज, हरपालपुर , श्रीमऊ और बरबन में आईटीआई की स्थापना, विधानसभा क्षेत्र में राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना, सवायजपुर, मैकपुर, दहेलिया,तिथिगांव, कैखाई, बमटापुर,अरवल सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर जूनियर हाईस्कूल की स्थापना के प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपे। श्री रानू ने इस बैठक में क्षेत्र में फसल अवशेष से बायो गैस बनाने के संयत्र स्थापित कराने, आयुष अस्पताल,मिनी स्टेडियम स्थापना की भी मांग की है। जिस पर मुख्यमंत्री ने शीघ्र कार्यवाही करवाने का आश्वासन दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजनाओं को धरातल पर उतारा – अजीत सिंह बब्बन

हरदोई (अंबरीष कुमार सक्सेना)

भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत आज चाय पर चर्चा कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने कहा है कि शक्ति वंदन कार्यक्रम समाज की महिलाओं के उस वर्ग तक पहुंचने का अभियान है जो लगातार सामाजिक कार्यों के माध्याम से आत्मनिर्भर बन समाज में अपने जैसी बहनों को प्रेरणा देने कार्य कर रही है। श्रीश चंद्र बरात घर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित शक्ति वंदन अभियान की बैठक में जनपद की स्वयं सहायता समूहों से आई महिलाओं ने चाय पर चर्चा के दौरान अपनी आर्थिक प्रगति एवं सशक्तिकरण की कहानी बयां की, स्वयं सहायता समूह की महिला लाभार्थियों ने बताया कि कैसे भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने उनके जीवन को बदलने और उन्हें समाज में अपनी पहचान बनाने का मौका दिया। बैठक में मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह से रीता सिंह, श्री श्याम स्वयं सहायता समूह से नंदनी अवस्थी, प्रिंसी स्वयं सहायता समूह से सोनी गुप्ता ने बताया कि भाजपा सरकार महिलाओं को आगे बढ़ने के भरपूर मौके मुहैया करा रही है। उन्होंने बताया कि डूडा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिला, समाज में उनकों एक पहचान मिली। उन्होंने बताया कि भाजपा की मोदी योगी सरकार ने उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप में सशक्त बनाने का काम किया। बेहतर कानून व्यवस्था होने से घर के बाहर बेझिझक होकर निकलती है। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने स्वयं सहायता समूहों से आई महिलाओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि देश की मातृ शक्ति जब सशक्त होगी तभी देश सशक्त बनेगा। इसी संकल्प को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारा। पूर्व की सरकारों ने महिलाओं को दबाने के लिए पुरुष प्रधान समाज की धारणा बना दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिथक को तोड़ने का काम किया। जात पात के भेद को मिटा सभी बहनों और माताओं को साशत और स्वावलंबी बनाने के लिए योजनाएं चलाई, जिसका परिणाम इस हाल में बैठी सैकड़ों महिलाओं के खिले चेहरे बयां कर रहे है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य पूरे देश में करोड़ों स्व–सहायता समूहों से संपर्क करके 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से जोड़ना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में भाजपा की कल्याणकारी योजनाओं का सबसे बड़ा हाथ बताते हुए कहा कि उज्जवला योजना से लेकर घरौनी योजना, हर घर जल योजना से लेकर सुकन्या समृद्धि योजना और नारी वंदन अधिनियम ने बहनों को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया है। पिछले दस सालों में भाजपा सरकार की नीतियों ने ऐसा वातावरण तैयार किया जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ने के भरपूर मौके मिले। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन महिला है, देश के आर्थिक तंत्र को संभालने वाली महिला है, खेल कूद में जनपद से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने अपनी क्षमता के झंडे गाड़ दिए है। हाई स्कूल, इंटर के रिजल्ट से लेकर आईएएस, पीसीएस के नतीजों में महिलाएं अव्वल स्थान हासिल कर रही है।

खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए – चंदन सेठ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिस तरह मनुष्य को जीवन जीने के लिए भोजन जरूरी है ठीक उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल भी जरूरी है। खेल के माध्यम से आपस में भाईचारा बढता है।खेल भी शिक्षा का एक अंग है। यह बातें शनिवार को केराकत में पौनी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि रियल हीरो की मिशाल पैदा करने वाले क्षेत्रिय फिल्म अभिनेताध्समाजसेवी चन्दन सेठ ने क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कही।पौनी प्रीमियर लीग के सौजन्य से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में बोलते हुए चन्दन ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए।हारने वाले को जीतने के लिए तथा जीतने वाले को जीत बरकरार रखने के लिए खेलना चाहिए। क्रिकेट देश में काफी लोकप्रिय खेल है और लगभग हर घर में इसके प्रेमी मिल जायेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अच्छा खिलाड़ी छोटे गांवों से भी निकल कर देश का नाम रोशन कर सकता है। उपरांत चन्दन ने फीता काटकर कर क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और खिलाडियों से परिचय किया। उद्घाटन मैच पौनी टीम तथा केराकत टीम के बीच खेला गया।इस दौरान सौरभ यादव प्रबन्धक श्री रामचरित्तर महा विद्यालय, राजू राठौर ग्राम प्रधान, शिवचन्द यादव अध्यक्ष व्यापार मंडल सरकोनी, सुदर्शन मिश्रा, दीपक दुबे, अरविन्द विश्वकर्मा,रोहित सेठ,टींकू गिरि,सोनू यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI सन्दर्भ संख्या – 24/234/2019/R/-1
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।